संक्षिप्त समाचार

अवैध रूप से भण्डारित 28 टन यूरिया बरामद

बिलासपुर। कृषि विभाग द्वारा तखतपुर विकासखण्ड के गनियारी में संचालित दो खाद दुकानों में भण्डारित 27.72 मीटरिक टन यूरिया खाद को जब्त कर इसके विक्रय पर रोक लगा दी गई है। स्त्रोत प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद दुकानदारों द्वारा इस खाद की बिक्री की जा रही थी। उप संचालक कृषि के निर्देश पर गनियारी में संचालित मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र एवं मेसर्स लवकेश खाद भण्डार का उर्वरक निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बीव्हीएफसीएल कम्पनी की यूरिया बगैर स्त्रोत प्रमाण पत्र के बेची जा रही थी। मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र में 10.35 मीटरिक टन एवं लवकेश खाद भण्डार में 17.37 मीटरिक टन यूरिया का अवैध स्टॉक दुकानों में पाया गया। गौरतलब है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार किसी भी खाद विक्रेता स्त्रोत प्रमाण पत्र के बगैर खाद बेचने की अनुमति नहीं है। फुटकर खाद विक्रेता को थोक विक्रेता से स्त्रोत प्रमाण पत्र प्राप्त कर और इसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही वह खाद बेच सकेगा।

महावीर इंटरनेशनल रायपुर मेन ने किया कंबल वितरण

रायपुर। महावीर इंटरनेशनल रायपुर मेन द्वारा गोलछा ट्रस्ट की ओर से सौ कंबल का आज रायपुर शहर मे ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्तियों को वितरित किया गया। जिसमें गोलछा ट्रस्ट की ओर से वीर प्रकाश गोलछा यस गोलछा। महावीर इंटरनेशनल रायपुर मैन के जोन चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हरितवाल इंटरनेशनल डायरेक्टर वीर रमेश भाई कोठारी वीर मदन तालेड़ा । वीर मनोज बोथरा सचिव एवं वीर पीयूष डागा कोषाध्यक्ष वीर महावीर कोचर आदि सदस्य उपस्थित थे।

राज्य ओपन स्कूल मुख्य एवं अवसर परीक्षा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2023 में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात 01 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक 500 रूपए विलंब शुल्क के साथ छात्र-छात्राएं परीक्षा आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। छात्र प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रो. व्ही.के. गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं और समीपस्थ अध्ययन केन्द्र में जमा कर सकते हैं।

एसएसपी ऑफिस की महिला एएसआई गिरफ्तार

बिलासपुर। पुलिसकर्मियों के फंड से हेराफेरी कर लाखों का गबन करने वाली महिला एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला एएसआई फंड शाखा प्रभारी के पद पर थी,जिसका फायदा उठा कर पुलिसकर्मियों के भविष्य निधि का गबन उसने एक हवलदार के साथ मिलकर कर लिया था। महिला एएसआई ने एसएसपी के जाली हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया था। मामले में सितंबर में एफआईआर दर्ज होने के बाद हवलदार संजय श्रीवास्तव को तो गिरफ्तार कर लिया गया पर महिला एएसआई तीन माह से फरार थी। जिसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। मधुशीला सुरजाल एएस आई (एम) के पद पर एसपी ऑफिस में पदस्थ थी। अपने पति की जगह उसे अनुकम्पा नियुक्ति मिली हुई थी। वह यहां फंड शाखा का प्रभार देखती थी। एसएसपी पारुल माथुर को एक दिन फंड शाखा के फाइलों के अवलोकन के दौरान उसमें कई कांट- झांट व गड़बड़िया मिली। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्तव को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। डीएसपी की जांच में इस बात की जानकारी मिली कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फण्ड शाखा प्रभारी सउनि (अ) मधुशीला सुरजाल अपने पदस्थापना के दौरान विभागीय भविष्य निधि के खाता धारकों के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि का आहरण एवं भुगतान गलत होना जानते हुए भी उनके द्वारा फण्ड शाखा में न्यस्त होकर वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है। तथा उनके द्वारा प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के बिना आवेदन किये नोट शीट तैयार कर उसके जी.पी.एफ खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद 15,75,000 रूपये की धनराशि स्वीकृत कर आहरण किया गया है तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते से भी पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद अधिक धनराशि का आहरण कर 59,75,000 का वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है।

राज्य सरकार के चार साल पूरे होने पर होंगे कई आयोजन

17 को मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 04 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसायटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय स्थलों, सभी जिलों में संचालित हाट-बाजारों, नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य की जनता के नाम संदेश भी देंगे।

छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के आयोजन की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके अनुसार राज्य के सभी गौठानों में 17 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे किसानों, गौठान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, पशुपालकों, भूमिहीन मजदूरों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों के सदस्यों, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों सहित स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया जाएगा एवं शासन द्वारा विगत 04 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही शासन की प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। दोपहर 3 बजे प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर, धान खरीदी केन्द्रों पर किसानों को आमंत्रित करके शासन की कृषि संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इत्यादि की जानकारी उन्हें दी जाएगी। प्रदेश के वन क्षेत्रों में इसी दिन सुबह 11 बजे तेंदुपत्ता संग्रहण केन्द्रों एवं वनोपज प्रबंधन समिति के कार्यालय स्थलों पर भी किसानों एवं मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में संचालित हाट बाजार स्थलों में भी लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सुबह 11 बजे से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्ड के निवासियों को आमंत्रित करते हुए शासन की 4 वर्षों की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया था। सरकार बनने के दो घंटे के भीतर ही ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, सिंचाई कर माफ करने जैसे वादे शासन ने पूरे कर दिए। सरकार ने उस वर्ष 2500 रुपए क्विंटल की दर से 80.37 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की थी। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करते हुए किसानों को फसलों पर इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। इस योजना के लागू होने के बाद हर साल किसानों की संख्या, खेती के रकबे और धान खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी होती गई। वर्ष 2019-20 में 84 लाख मीटरिक टन, 2020-21 में 92 लाख मीटरिक टन, 2021-22 में 98 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल 110 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चार सालों में अब तक 16,401 करोड़ 45 लाख रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों, वृक्षारोपण और कोदो-कुटकी-रागी को भी शामिल कर लिया गया है। अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 लाख 82 हजार किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ कर दिया था।

इसी तरह 17 लाख से अधिक किसानों पर वर्षों से बकाया 244 करोड़ 18 लाख रुपए का सिंचाई कर भी दो घंटे के भीतर माफ कर दिया। इसके बाद वर्ष 2018 से जून 2021 तक का 80 करोड़ रुपए का और बकाया सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया।

दुर्गा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जाना किन्नरों का इतिहास

रायपुर। मितवा संकल्प समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना दुर्गा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के साथ ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने किन्नरों के इतिहास में जाना। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में रवीना बरिहा सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, मितवा संकल्प सेवा समिति की अध्यक्ष विद्या राजपूत प्राचार्य डॉ. प्रतिभा मुखर्जी साहूकार उपस्थित थी।रवीना ने बताया कि वह इस कॉलेज के विद्यार्थी रही हैं और वह जब इस कॉलेज में पढ़ती थी तब उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था। लेकिन स्कूली जीवन में उन्हें काफी अपमान सहना पड़ा है एवं उनके साथ कोई खेलता नहीं था। उन्होंने बताया कि 3000 वर्ष पूर्व के इतिहास को हम देखें तो किन्नरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। रामायण, महाभारत, मुगल शासन, क्रिश्चियन समुदाय, बौद्ध समुदाय में भी सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजों के काल में 1871 अपराधिक जनजाति अधिनियम के कारण ट्रांसजेंडर की स्थिति खराब हुई है। हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा में 3 जेंडर का उल्लेख है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं उभयलिंगी, पर अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी की तो उसमें सिर्फ दो ही लिंग की बात होती है। समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर अधिनियम पारित करवाया गया साथ ही इस एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विद्या राजपूत ने बताया कि किस तरह से स्कूल में उनके साथ एवं घरवालों का व्यवहार होता था, आज वह शेल्टर होम और गरिमा गृह का संचालन कर रही है, जहां पर ट्रांसजेंडर रहकर पढ़ाई लिखाई के साथ अपने इंटरेस्ट के विषयों पर प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद उन्हें जॉब दिलाया जाता है। आज पुलिस विभाग के अलावा वेदांता, बाल्को, शुभम के मार्ट आदि अन्य स्थानों पर काम कर वह अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता - साहू संघ

रायपुर। वर्तमान में आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में ज्वलंत हो गया है, राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर छत्तीसगढ़ के सामाजिक संरचना का दृष्टि से एसटी 32 प्रतिशत, एससी 13 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत एवं ईडब्ल्यूएस 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को भेजा गया है। जिस पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

मंडल-आयोग ने भी ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत का प्रावधान किया है। वर्तमान में जब केंद्र सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दे रही है तो छत्तीसगढ़ तो ओबीसी बाहुल्य राज्य है यहां ओबीसी का आबादी 52 प्रतिशत है तो आरक्षण उसका लगभग आधा

27 प्रतिशत दिया जाना ओबीसी का हक है। राज्यपाल का यह कहा जाना और भी दुर्भाग्यजनक है कि मैंने केवल आदिवासी आरक्षण के लिए कहा था, यह पिछड़ा वर्ग का अपमान भी है। उक्त बातें छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू ने पत्रकारवार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को बहुसंख्यक समाज की भावना और अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ओबीसी समाज कभी भी आदिवासी आरक्षण का विरोध नहीं किया है इसलिए जब ओबीसी की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक वर्ग के हित की भी चिंता करनी चाहिए। ओबीसी आरक्षण का मुख्य आधार शैक्षणिक और सामाजिक, पिछड़ापन है जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी व्याप्त है, ओबीसी आरक्षण संवैधानिक हक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर आरक्षण बिल का अनुमोदन करें, यही जनभावना का सम्मान है। सकारात्मक परिणाम नहीं होने पर अब ओबीसी समाज चुप नहीं बैठेगा। इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो साहू समाज पीछे नहीं हटेगा।

उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण पर कोई न्यायालयीन बात आती है तो हम तर्क संगत बात रखेंगे। जब झारखंड राज्य 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर सकता है तो छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण पर क्यों तर्क-कुतर्क होना चाहिए। अन्य विषयों पर बेवजह कुतर्क करने के बजाए हम सब को, सभी दलों तथा सर्वसमाज को समवेत रुप से प्रयास कर छत्तीसगढ़ को 9वीं अनुसूचि में सम्मिलित कराने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रयास करना चाहिए।

रोहन ने हासिल किया गोल्ड मेडल के साथ प्रो कार्ड

रायपुर। हाल ही में गोवा में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में शहर के रोहन यदु ने दो गोल्ड मेडल के साथ प्रो कार्ड हासिल किया। इससे पूर्व भी रोहन ने मुंबई में पिछले महीने संपन्न हुई इसी स्पर्धा में प्रो कार्ड हासिल किया था। प्रो कार्ड हासिल करने वाले रोहन छत्तीसगढ़ के एक मात्र खिलाड़ी है। गोवा में 10 व 11 सितंबर को आयोजित आईसीएन में देश भर से 1100 खिलाड़ी शामिल हुए। अलग-अलग 10 कैटेगिरी में खिलाडियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। रोहन यदु ने 30 से 35 वर्ष आयु वर्ग में गोल्र्ड, ओपन कैटेगिरी में भी गोल्ड हासिल किया। इसके अलावा क्लासिक फैजिस्ट में चौथे स्थान हासिल किया। ओवर ऑल कैटेगिरी में रोहन यदु ने शानदार प्रदर्शन किया जिसके आधार पर उन्हें प्रो कार्ड प्राप्त हुआ। प्रो कार्ड प्राप्त होने वाले खिलाडियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शिरकत करने का अवसर मिलता है। रोहन यदु बॉडी बिल्डर होने के साथ-साथ एक कुशल तैराक भी है और तैराकी में भी उन्होंने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है। रोहन क्रिज कैटिंग जीम में नियमित रुप से 2 से 3 घंटे तक अभ्यास करते हैं, साथ ही वे खिलाडियों को भी बॉडी बिल्डिंग का प्रशिक्षण भी देते हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है और यह ओपन है। आईसीएन के वर्तमान अध्यक्ष जय आचार्य है जिन्होंने गोवा में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। छत्तीसगढ़ से रोहन के अलावा डा. सुषमा पचौरी व नवजीत चावला ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

जनदर्शन में सुनी आम जनता की समस्याएं

बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज यहां जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में शहर सहित दूर-दराज से पहुंचे लोगों से मुलाकात कर बड़े इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने तत्काल हो सकने वाले कुछ आवेदनों का जहां जनदर्शन में ही समाधान कर दिया वहीं जांच एवं परीक्षण की जरूरत वाले कुछ गंभीर किस्म के मामलों को टीएल में पंजीकृत करते हुए निराकरण के लिए अधिकारियों को समय-सीमा दी। जनदर्शन में आज कलेक्टर ने 122 निजी और सामुदायिक मामलों की सुनवाई की।

उन्होंने 24 लोगों को मौके पर ही राशनकार्ड बनवाकर दिया, जिससे सभी ने खुश होकर त्वरित सुनवाई के लिए कलेक्टर को धन्यवाद दिया। आज जनदर्शन में कलेक्टर से मुलाकात कर विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम पंचायत विद्याडीह की सरपंच श्रीमती सत्यवती गोस्वामी ने धान संग्रहण केंद्र विद्याडीह एवं मुक्तिधाम में हैण्डपंप खनन की मांग की। कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को

आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत मल्हार के वार्ड क्रमांक 7 के 68 वर्षीय वृद्ध श्री दशरथ लाल और वृद्धा श्रीमती ललीता श्रीवास ने कलेक्टर के समक्ष अपनी रूकी हुई वृद्धा पेंशन की राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने मामले को टीएल में लेते हुए सीएमओ मल्हार को पेंशन का निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम रमतला निवासी श्री संतोष सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ दिलाने की गुहार लगाई।

इस प्रकरण को उप संचालक कृषि देखेंगे। खमतराई निवासी श्रीमती कुमारी श्रीवास ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपने पुत्र को नशा मुक्ति केंद्र भेजने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र राजकुमार गलत संगत में पड़कर नशे का आदी हो गया है और मुझसे मारपीट भी करता है। कलेक्टर ने मामले को टीएल में लेते हुए समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रतनपुर तहसील के करैहापारा निवासी श्री दिलीप कुमार तिवारी ने रतनपुर सोसायटी द्वारा धान खरीदी टोकन नहीं देने की शिकायत की। इस मामले को एसडीएम कोटा देखेंगे। बोदरी तहसील के बोड़सरा निवासी श्री प्रहलाद सोनवानी ने स्वरोजगार के लिए लोन राशि दिलाने की अर्जी लगाई। कलेक्टर ने अंत्यावसायी विभाग को मामले का निराकरण करने कहा। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसोड़ी की सरपंच ने परसोड़ी में आवागमन सुविधा के लिए पुलिया निर्माण और गोठान समतलीकरण कार्य करवाने आवेदन दिया। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगोई की सरपंच ने शासकीय जमीन का सीमांकन करवाने का आवेदन दिया।

तीन पखवाड़े में किसानों से 43.74 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आकड़ा अनुमानित लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। धान खरीदी महाअभियान के महज तीसरे पखवाड़े तक 43 लाख 73 हजार 591 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में राज्य के 11 लाख 42 हजार 055 किसानों को 9057 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री के मागदर्शन में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ था। किसानों को धान विक्रय में सहुलियत एवं मिलर्स के धान उठाव के लिए बारदाने की भी बेहतर व्यवस्था के कारण सफलतापूर्वक धान की खरीदी एंव कस्टम मिलिंग हुई थी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक के धान खरीदी में से 50 प्रतिशत से अधिक धान का उठाव हो चुका है।

खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए सामान्य टोकन के साथ ही ऑनलाइन टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है। जिसके चलते किसानों को सहूलियत होने लगी है। बड़ी संख्या में किसान टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से धान बेचने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक तिथि का चयन कर रहें हैं। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2594 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है।

संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का रंगारंग शुभारंभ

बिलासपुर। संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल आज स्वर्गीय बी.आर.यादव स्मृति स्टेडियम बहतराई में उत्साह के साथ शुरू हुआ। पहले दिन आज महिला खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धाएं हुई। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। राज्य स्तरीय टीम में चयन की घोषणा भी की गई। जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मौजूद रहकर परम्परागत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रत्येक खेल को तीन आयु समूह में बांटकर उनके बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुभारंभ समारोह के अवसर पर विधायक शैलेश पाण्डेय ने सम्बोधित करते हुए कहा कि टीवी एवं मोबाईल ने हमें अपने ग्रामीण खेलों को दूर ढकेल दिया है। टीवी में हम स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल देखते हैं।

और उसी का अपने जीवन में भी अनुकरण कर खेल आयोजित करते हैं। नये-नये खेलों से हमारे पारम्परिक खेलों का नुकसान हुआ है। लोग इन्हें भूलने लगे थे। ऐसी हालात में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इन्हें बचाने के लिए सामने आये। उन्होंने ग्रामीण खेलों को पहचान देकर गांव-गांव में इनकी प्रतियोगिताएं कराई। उत्साह के साथ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने इनमें हिस्सेदारी कर अपने पुराने दिनों को फिर से याद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को इन प्रयासों के लिए बधाई भी दी। मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खेलों से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ये हमारी अस्मिता एवं स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। खेलों से हमें हमारी क्षमता प्रदर्शित करने का अच्छा मौका मिलता है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की विलुप्तप्राय पारम्परिक खेलों को पुनर्जीवित कर ऐतिहासिक काम किया है। समाज के सभी वर्ग के लोग इन खेलों में उल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। ये न केवल खेल है बल्कि हमारी संस्कृति एवं परम्परा का अटूट हिस्सा है। इन खेलों को जीकर के हमारे पूर्वजों का शरीर स्वस्थ रहा है।

उपार्जन केंद्र पोड़ी में 291 कट्टी धान जप्त

- *कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम द्वारा लगातार किया जा रहा निरीक्षण

बिलासपुर। बिचौलियों द्वारा किसानों के पर्ची पर धान न बेचे जाने संबंधी कलेक्टर बिलासपुर व एसडीएम कोटा के निर्देशानुसार जांच टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में जांच के दौरान कृषक श्रीमती बेचन बाई व सुशील मानिकपुरी का धान सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में विक्रय हेतु 12 दिसम्बर 2022 के लिए काटा गया था निरीक्षण में उक्त टोकन के विरुद्ध 141 बोरा धान कट्टी किस्म मोटा पतला एवं 150 कट्टी किस्म मोटा पतला जिसका क्रमशरू ड्राइवर रोहित कुमार सद्दाम हुसैन द्वारा लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ड्राइवर द्वारा किसान का धान न होकर हरिकिशन ट्रेडर्स से धान उपार्जन केंद्र

लाया स्वीकार किया गया। संयुक्त टीम के जांच के समय उक्त किसान अनुपस्थित पाए गए तथा कोई भी व्यक्ति धान का स्वामित्व का प्रमाणित दस्तावेज नहीं कर पाया जिसके कारण छत्तीसगढ़ धान उपार्जन नीति एवं मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के तहत कुल 291 कट्टी धान जप्त कर प्रभारी प्रबंधक अनुराग जायसवाल धान उपार्जन केंद्र पौड़ी को सुपुर्द एवं सुरक्षित हेतु दिया गया उक्त धान आगामी निराकरण तक धान उपार्जन केंद्र पोड़ी में सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। संयुक्त जांच दल में तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत, मुजाहिद हुसैन मंडी निरीक्षक, नीतीश कुमार नामक मंडी उपनिरीक्षक केशवराज खरकर, मंडी उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह मंडी कर्मचारी शेख अब्दुल कादिर खाद्य निरीक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।